

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

01.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00 बजे

विधानसभा

प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शिमला में जारी है। सत्र में आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी

बजट सत्र में आज सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों द्वारा 19 प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, जिनमें मुख्यतः कचरा प्रबंधन, खाली पदों को भरने, वेतन भत्ते व पेंशन, दूध खरीद, करुणामूलक नियुक्तियां, बस रूट, बंदोबस्त और मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य मुद्दे शामिल रहेंगे। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विभिन्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा नियम-62 के तहत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और केवल सिंह पठानिया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। वहीं, नियम 130 के तहत विधायक जीत राम कटवाल और नियम 61 के तहत विधायक बिक्रम सिंह और सतपाल सिंह सत्ती अपने-अपने विषय उठाएंगे। सदन में 3 सरकारी विधेयकों को पुर्नस्थापित और एक विधेयक को चर्चा के उपरांत पारित किया जाएगा।

एंटी टैक्स

एंटी टैक्स पर चल रहे गतिरोध के बीच प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों की 5 से 12 सीटर गाड़ियों के प्रवेश शुल्क को कम कर दिया है। नई दरों के अनुसार आज से हिमाचल पहुंचने वाली पांच से 12 सीटर क्षमता वाले निजी वाहनों को अब 100 रुपये प्रवेश शुल्क चुकाना होगा। इससे पहले पांच सीटर वाली गाड़ी को 70 जबकि 12 सीटर गाड़ी को 110 रुपये शुल्क चुकाना पड़ रहा था। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों इन दोनों श्रेणियों की गाड़ियों के प्रवेश शुल्क को बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया था, जिसका लगातार विरोध हो रहा था।

जनगणना

विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या प्रक्रिया, जनगणना-2027 का पहला चरण आज से शुरू होगा। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए पहली मार्च, 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। पहली बार, जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह स्व-गणना आज से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण में सभी भवनों और संरचनाओं की सूची तैयार की जाएगी तथा आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। भवनों की जियो-टैगिंग भी की जाएगी और हर संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। देशभर में इस कार्य के लिए तीस लाख से अधिक गणनाकर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही, नागरिक सोलह भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 के लिए ग्यारह हजार सात सौ अठारह करोड़ रुपये से अधिक राशि को मंजूरी दी है।

वित्तीय नियम बदलाव

आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही, वित्तीय नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों सहित कई सुधार लागू हो गए हैं। एक रिपोर्ट—

पंचायत चुनाव आरक्षण

प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए रोस्टर व्यवस्था में संशोधन का अधिकार जिला उपायुक्तों को दे दिया है। संशोधित नियमों के तहत 95 प्रतिशत पंचायतों का आरक्षण नियमों के तहत होगा, जबकि 5 प्रतिशत पंचायतों में उपायुक्त भौगोलिक व अन्य वशिष्ठ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण रोस्टर बदल सकेंगे। पंचायती रात विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब उपायुक्त विशेष परिस्थितियों में पंचायतों के रोस्टर में सीमित बदलाव कर सकेंगे। सरकार ने पंचायती राज चुनाव संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के रोस्टर में अधिकतम पांच प्रतिशत तक परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये संशोधन नियमों में पूर्व में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद किया गया है।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीती रात कहीं-कहीं आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज व कल पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी का अनुमान जताया है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। 3 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 व 4 अप्रैल को प्रदेश के 10 जिलों में आंधी-बिजली व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है।

.....